The Dialogue™

INFORM ENGAGE IDEATE

व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2019 कौ सार

व्यापार निहितार्थ

1. परिचय

भारत के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 ("विधेयक") पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट दो साल के व्यापक विचार-विमर्श के बाद संसद में पेश की गई है। इस विधेयक को लागू करने का उद्देश्य और कारण 24 अगस्त 2017 से जुड़ा है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ पर अपना फैसला सुनाया था। निर्णय ने भारत सरकार को नागरिकों की सूचनात्मक गोपनीयता की रक्षा के लिए एक मजबूत डेटा सुरक्षा व्यवस्था लाने का भी निर्देश दिया।
जैसे-जैसे भारत एक डेटा सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, विधेयक के कुछ व्यवसाय-संबंधी विचारों पर विमर्श करना आवश्यक है, ताकि संतुलित समझौते स्वीकार हो सके, और डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक हितों की रक्षा के माध्यम से नवाचार सक्षम हो पाए | इस प्राइमर में चर्चा की गई व्यापार से संबंधित विचारों के तहत कुछ प्रासंगिक तत्व है, अनुपालन लागत, स्टार्ट-अप की स्थिति, सीमा पार डेटा प्रवाह, विधेयक के दायरे में गैर-व्यक्तिगत डेटा को शामिल करना।

2. व्यापार से संबंधित विचार

2.1. सीमा पार डेटा प्रवाह

राष्ट्रीय सीमाओं के पार सूचनाओं की आवाजाही आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करती है और यह सीमा पार डेटा प्रवाह पर आधारित है। एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सक्षम करने के उद्देश्य के लिए डेटा के मुक्त प्रवाह को सुगम बनाना फायदेमंद होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सबसे बड़े लाभार्थी होंगे (ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से) क्योंकि वे वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में सक्षम होंगे, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों तक पहुंचेंगे, जो अन्यथा उनके लिए दुर्गम होगा। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 2016 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया था कि सीमा पार डेटा प्रवाह में बाधाओं को दूर करने से 2.89 मिलियन नई कंपनियां (मुख्य रूप से एमएसएमई) बन सकती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सीमा पार प्रौद्योगिकियों पर निर्भर कंपनियों की जीवित रहने की दर (54%) ऑफ़लाइन कंपनियों की तुलना में अधिक थी। लेकिन विधेयक में सीमा पार डेटा प्रवाह के प्रावधान इन आदर्शों के विपरीत हैं और विभिन्न मुद्दों का कारण बनेंगे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

सुरक्षा विरोधाभास: विधेयक संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। विधेयक में, 'केवल' शब्द को हटा दिया गया है, इसलिए संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को अन्य जगहों पर भेजा जा सकता है। जहां तक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा का संबंध है, कुछ स्थितियों को छोड़कर, केवल भारत में संग्रहीत किया जा सकता है। हालांकि, सीमा पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध लगाने से न तो डेटा की अतिरिक्त सुरक्षा/गोपनीयता और/या उस तक पहुंच में वृद्धि होती है। हालांकि अक्सर ऐसा माना जाता है, डेटा की सुरक्षा, इसपर निर्भर नहीं है कि इसे कहाँ संग्रहीत किया जाता है।

प्रक्रिया में देरी: वर्तमान में, अनुबंधों के अनुसार किए गए सीमा-पार हस्तांतरण के लिए डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है। डेटा के सीमा पार हस्तांतरण की सुविधा के लिए संविदात्मक खंडों का उपयोग आम है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां प्रत्येक कंपनी को सीमा पार संविदात्मक संबंधों और विलेखों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण से अनुमोदन लेना होगा। इसलिए, प्राधिकरण अनुरोधों से भर जाएगा, जो अंततः विदेशी कंपनियों के साथ अनुबंधों को पूरा करने में देरी करेगा। यह व्यापार करने में आसानी में सुधार के भारत के दृष्टिकोण के लिए हानिकारक हो सकता है।

हमारी सिफारिशें

- ऐसे उपकरण विकसित करें जो सीमा पार डेटा प्रवाह की अनुमति दें- जिसमें अंतर-संचालन योग्य डेटा सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना, पर्याप्तता निर्णयों के आधार पर डेटा साझाकरण समझौते आदि शामिल हैं।
- ऐसे डेटा को संक्षिप्त रूप से निर्दिष्ट करें जिसे साझा नहीं किया जा सकता- जो भारत के लिए रणनीतिक महत्व का है।

2.2. विधेयक से गैर-व्यक्तिगत डेटा (एनपीडी) साझाकरण को हटाना

विधेयक की प्रस्तावना व्यक्तिगत डेटा के अभिशासन और अपने नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए इसके दायरे को परिभाषित करती है। सरकार के पास, कंपनियों को अपने गैर-व्यक्तिगत डेटा साझा करने का निर्देश देने की ताकत देते हुए, विधेयक अपने दायरे से बाहर जाता है और विभिन्न मुद्दों का कारण बनता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

प्रौद्योगिकी पर रोक: गैर-व्यक्तिगत डेटा के अभिशासन की अनुमति देने के लिए, प्रस्तावना के दायरे का विस्तार, गैर-व्यक्तिगत डेटा तक सरकारी पहुंच से जुड़ी मूलभूत समस्या का समाधान नहीं करता है । यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ संघर्ष करता है जो कंपनियों को उनकी मालिकाना जानकारी पर है । इन अधिकारों के साथ यह टकराव व्यवसायों को नए और नवीन डेटा-आधारित उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन से भी हतोत्साहित करेगा क्योंकि डेटा पर उनका निवेश अब प्रकटन सम्बन्धी आदेशों के साथ आकर्षक नहीं होगा।

पुनः पहचान का खतरा: उपयुक्त सुरक्षा उपायों के अभाव में, इस तरह की पहुंच गंभीर जोखिम भी पैदा करती है, क्योंकि पुनः पहचान तकनीकों से व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एकत्रित और अज्ञात डेटासेट का उपयोग किया जा सकता है।

एनपीडी को विनियमित करने की जटिलता: यह एक बहुत ही जटिल विषय बन जाता है, जिसके कार्यान्वयन के लिए व्यापक परामर्श और विश्लेषण की आवश्यकता है। सरकार के साथ गैर-व्यक्तिगत डेटा साझा करने से समाज के लिए वैध लाभ हो सकते हैं, जैसे कि बेहतर सेवा वितरण प्रदान करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करना, पर यह एक परिभाषित ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए जो व्यवसायों को पर्याप्त सौदेबाजी की शक्ति दे। इसे छोड़कर, यह भारत में नए घरेलू और विदेशी निवेश दोनों में व्यवसायों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और भारत में व्यापार बढ़ाने की सरकार की भावना के खिलाफ पूरी तरह से काम कर सकता है।

एनपीडी शासन ढांचे के साथ संघर्ष: चूंकि क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की एक अलग समिति गैर-व्यक्तिगत डेटा के लिए शासन ढांचे पर विचार कर रही है, इसलिए विधेयक को गैर-व्यक्तिगत डेटा पर प्रावधान करने से बचना चाहिए । विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह भी सिफारिश की थी कि गैर-व्यक्तिगत डेटा से संबंधित किसी भी प्रावधान को विधेयक से हटाना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये दोनों ढांचे परस्पर अनन्य हैं फिर भी सद्भाव में काम करते हैं।

हमारी सिफारिशें

- डेटा सुरक्षा और गैर-व्यक्तिगत डेटा साझाकरण के ढांचे को अलग करना । पर्याप्त परामर्श और विचार से पहले दोनों का संयोजन व्यापक भ्रम पैदा कर सकता है।
- निर्बाध कार्यान्वयन के लिए एनपीडी शासन और विधेयक के प्रावधानों को सुसंगत बनाना।
- ऐसे किसी भी डेटा साझाकरण ढांचे को विकसित करने में, सरकार को मालिकाना डेटा (जैसे एल्गोरिथम, व्यापार रहस्य, गोपनीय जानकारी, ग्राहक/विक्रेता सूची, आदि) साझा करने से जुड़ी चिंताओं पर विचार करना चाहिए, जो व्यवसाय चलाने के लिए महत्वपूर्ण है।

2.3. कार्यान्वयन समय सीमा

विधेयक के बड़े और छोटे दोनों तरह के उद्योगों के लिए भारत के संपूर्ण डिजिटल परिदृश्य में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। यह देखते हुए कि विधेयक अपनी व्यापक पहुंच के माध्यम से संगठनों की प्रकृति और कार्यप्रणाली को मौलिक रूप से बदल सकता है, उन संगठनों, उद्यमों और उद्योग निकायों को, जो विधेयक के दायरे में काम कर रहे हैं या प्रभावित है, विधेयक के बुनियादी सिद्धांतों और आवश्यकताओं को समझने के साथ-साथ इसके अनुकूल होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (ईयू जीडीपीआर), जो 2018 में लागू हुआ, उसने 2 साल का समय प्रदान किया था। जबकि विधेयक चरणबद्ध कार्यान्वयन को संदर्भित करता है, न केवल अधिनियम के प्रावधानों के लिए, बल्कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी भी नियम के लिए पर्याप्त समयसीमा के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए; अन्यथा, यह विभिन्न नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

एएक आकार सभ‍ी मुद्दों के लिए: भारत में, गोपनीयता व्यवस्था का कार्यान्वयन नियामकों और घरेलू उद्योगों के लिए एक नई शुरुआत है। इस विधेयक को सीखने और पालन करने के लिए ऑटोमोटिव, रिटेल, ऑयल एंड गैस, पीएसयू, पावर कंपनियों, स्वास्थ्य सेवाओं और कई अन्य से लेकर डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के उद्योगों की आवश्यकता होगी। इसलिए, विधेयक के प्रावधान एक तरह के नहीं हो सकते हैं, जहां इसे क्षैतिज (क्षेत्रों के भीतर सरकारी संस्थाओं सहित) और लंबवत (विभिन्न क्षेत्रों में) रूप से तैयार और संचालित करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और अनुकूलन की आवश्यकता होगी।

समयरेखा मुद्दा: जीडीपीआर अनुभव को देखते हुए, ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो अनुपालन के लिए एक स्पष्ट समयरेखा प्रदान करें, जो कंपनियों को, विशेष रूप से स्टार्ट-अप को, अपने डेटा प्रसंस्करण तंत्र में संशोधन करने के लिए आवश्यक पर्याप्त समय के साथ अनुमति दे ताकि आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसी तरह, बड़ी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, अपने आईटी सिस्टम को एकीकृत करने और कई देशों के साथ अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यदि कार्यान्वयन के लिए अनुमत समय अपर्याप्त है, तो यह न केवल कुछ गतिविधियों को रोक सकता है, बल्कि डेटा प्रसंस्करण के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

हमारी सिफारिशें

- संस्थाओं को किसी विशेष मानक/आचार संहिता या नियम की अधिसूचना की तारीख से तैयार करने और उसका पालन करने के लिए न्यूनतम 24 महीने का समय होना चाहिए।
- चरणबद्ध कार्यान्वयन निम्न तरीके के समान होना चाहिए:
- चरण 1: प्राधिकरण के गठन के लिए समयसीमा प्रदान करें
- चरण 2: किसी विशेष नियम/मानकों/आचार संहिता को लागू करने के लिए अधिसूचना की तारीख से 24 महीने की न्यूनतम अवधि बताएं। (इस अवधि में हितधारक परामर्श शामिल नहीं होगा जो प्राधिकरण को ऐसे मानक/आचार संहिता या नियम की अधिसूचना से पहले करना चाहिए।)
- दुसरे देशों के डेटा से निपटने वाले डेटा प्रसंसक के लिए अतिरिक्त समय; अतिरिक्त समय-सीमा की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस तरह के परिवर्तनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों पर पुन: वार्ता की आवश्यकता होगी।

एएक आकार सभ‌ी मुद्दों के लिए: भारत में, गोपनीयता व्यवस्था का कार्यान्वयन नियामकों और घरेलू उद्योगों के लिए एक नई शुरुआत है। इस विधेयक को सीखने और पालन करने के लिए ऑटोमोटिव, रिटेल, ऑयल एंड गैस, पीएसयू, पावर कंपनियों, स्वास्थ्य सेवाओं और कई अन्य से लेकर डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के उद्योगों की आवश्यकता होगी। इसलिए, विधेयक के प्रावधान एक तरह के नहीं हो सकते हैं, जहां इसे क्षैतिज (क्षेत्रों के भीतर सरकारी संस्थाओं सहित) और लंबवत (विभिन्न क्षेत्रों में) रूप से तैयार और संचालित करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और अनुकूलन की आवश्यकता होगी।

समयरेखा मुद्दा: जीडीपीआर अनुभव को देखते हुए, ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो अनुपालन के लिए एक स्पष्ट समयरेखा प्रदान करें, जो कंपनियों को, विशेष रूप से स्टार्ट-अप को, अपने डेटा प्रसंस्करण तंत्र में संशोधन करने के लिए आवश्यक पर्याप्त समय के साथ अनुमति दे ताकि आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसी तरह, बड़ी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, अपने आईटी सिस्टम को एकीकृत करने और कई देशों के साथ अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यदि कार्यान्वयन के लिए अनुमत समय अपर्याप्त है, तो यह न केवल कुछ गतिविधियों को रोक सकता है, बल्कि डेटा प्रसंस्करण के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

हमारी सिफारिशें

- संस्थाओं को किसी विशेष मानक/आचार संहिता या नियम की अधिसूचना की तारीख से तैयार करने और उसका पालन करने के लिए न्यूनतम 24 महीने का समय होना चाहिए।
- चरणबद्ध कार्यान्वयन निम्न तरीके के समान होना चाहिए:
- चरण 1: प्राधिकरण के गठन के लिए समयसीमा प्रदान करें
- चरण 2: किसी विशेष नियम/मानकों/आचार संहिता को लागू करने के लिए अधिसूचना की तारीख से 24 महीने की न्यूनतम अवधि बताएं। (इस अवधि में हितधारक परामर्श शामिल नहीं होगा जो प्राधिकरण को ऐसे मानक/आचार संहिता या नियम की अधिसूचना से पहले करना चाहिए।)
- दुसरे देशों के डेटा से निपटने वाले डेटा प्रसंसक के लिए अतिरिक्त समय; अतिरिक्त समय-सीमा की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस तरह के परिवर्तनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों पर पुन: वार्ता की आवश्यकता होगी।

2.4. भारत में स्टार्ट-अप और व्यापार करने में आसानी

2021 तक, वैश्विक स्तर पर लगभग 490+ यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जिनमें से 25+ भारत में हैं, जिससे भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है - केवल चीन और यूएसए के बाद। भारत के लिए 2017 से 2018 तक जो बदलाव आया, वह था एड-टेक, फूड डिलीवरी, बी 2 बी, हेल्थ टेक, इंसुरटेक, आदि जैसे नए और विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल करना। इसके अलावा, पहले से ही संपन्न इंटरनेट सॉफ्टवेयर और सेवाओं का गढ़ - ई-कॉमर्स और मार्केटप्लेस और फिनटेक, में केवल वृद्धि हुई है। चूंकि भारत एक स्टार्ट-अप हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, इसलिए विधेयक अधिनियमन के साथ स्टार्ट-अप के लिए उभर रहे निम्नलिखित मुद्दों को दूर करना महत्वपूर्ण है।

छूट बनाम गोपनीयता: परिभाषाओं में अस्पष्टता, सख्त अनुपालन, आईपी अधिकारों का हनन स्टार्ट-अप के लिए समस्याग्रस्त साबित होते हैं। विधेयक में महत्वपूर्ण डेटा न्यासियों को पंजीकरण प्राप्त करने, स्वतंत्र ऑडिट करने और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने का आदेश दिया गया है। इससे स्टार्ट-अप के लिए अनुपालन लागत में वृद्धि होने की संभावना है, जो उनके उपलब्ध संसाधनों और निधियों के अनुरूप नहीं हो सकता है। विधेयक का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना होना चाहिए, जिससे अधिक निवेश आमंत्रित हो सकें। इसके अलावा, कुछ अनुपालनों से छूट इस तरह से होनी चाहिए कि यह व्यक्तियों की गोपनीयता के प्रतिकूल न हो, लेकिन साथ ही स्टार्ट-अप के लिए फायदेमंद हो।

परिवर्तन की लागत: स्टार्ट-अप को विधेयक के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहायता और नियामक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। स्टार्ट-अप के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत डेटा संरक्षण से प्रस्तावित विधेयक तक एक सुचारू परिवर्तन से गुजरने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी, विभिन्न सत्र और ज्ञान सामग्री द्वारा। तकनीकी कर्मियों के अलावा, उन्हें नियामक विशेषज्ञों को नियुक्त करना होगा, जिन्हें स्टार्ट-अप से अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। इन पूंजी बाधाओं के बावजूद, नियामक अनुपालन लागत स्टार्ट-अप के कार्यों को भी प्रभावित करेगी। फिर भी, यह परिवर्तन स्टार्ट-अप और एसएमई के लिए विकल्पों की खोज शुरू करने और विधेयक के संबंध में अपने वर्तमान डेटा सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन करने के लिए एक उचित प्रारंभिक बिंदु प्रदान करेगा।

हमारी सिफारिशें

- स्टार्ट-अप और एमएसएमई समुदायों की परेशानियों को कम करने के लिए, अलग-अलग और शिथिल अनुपालन मानक तैयार किया जाना चाहिए। यह एक वित्तीय सीमा पर आधारित हो सकता है और इन कंपनियों को अनुपालन की योजना बनाने और अपने व्यवसाय में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- बिल के तहत देनदारी व्यवस्थाओं पर फिर से विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गैर-अनुपालन से प्राधिकरण के द्वारा कठोर उपाय किए जा सकते हैं। यह नवाचार को प्रभावित करेगा, क्योंकि कई आपराधिक मुकदमा चलाने से डरते होंगे।

पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा देखे जाने वाले शीर्ष 10 थिंक टैंकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

21वीं सदी में तेजी से तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अनूठी समस्याओं को हल करने के लिए 'डायलॉग' भारत में सुसंगत सार्वजनिक नीति प्रवचन बनाता है। 'डायलॉग' का मिशन लोगों के लिए नीति लाना है और बाद में उन्हें उन मुद्दों से जोड़ना है जो आज की दुनिया में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सूचित जनमत और नागरिक भागीदारी के माध्यम से सुधारों को चलाने का दीर्घकालिक उद्देश्य है।

अधिक जानने के लिए
www.thedialogue.co पर जाएं,
या मेल करें info@thedialogue.co

The Dialogue™
INFORM ENGAGE IDEATE